

दिल्ली कायाविवरण :
फोन नम्बर:-011-30712200, 45212200,
फैक्स नम्बर:-011-30712224
विज्ञान विभाग:-011-30712229
सामुदायिक विभाग:-011-30712292-93
पेनसिल विभाग:-011-30712330
समय :- 91-11-30712290, 30712384,
 011-45212383, 84
E-mail:- Editor@punjabkesar.com

उत्साह से मतदान

बिहार में पहले चरण के मतदान का शांतिपूर्वक संपन्न होना सुखद और प्रशंसनीय है। शाम पाँच बजे तक हुए 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान से स्पष्ट हो गया कि अंतिम रूप से इस बार मतदान प्रक्रिया सहजानी रहने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान से विश्वसनीय को कान खड़े हो गए हैं, तो आश्चर्य नहीं। पहले चरण के मतदान में बड़ी संख्या में महिलाओं को वोट डालते देखा गया है, इससे भी कमाई को बल मिला है। बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 121 पर मतदान हुआ है। जिसमें मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और प्रमुख विपक्षी महागठबंधन के बीच है और तीसरे पक्ष के रूप में जन सुरज पार्टी भी अपना भाग्य आजमा रही है। इस बार बागी भी बड़ी संख्या में खड़े हैं, तो वोट कटने को आशाओं से विश्वसनीय की जटिलता बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर मतदान के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि बिहार में हवा किसके पक्ष में बह रही है? हर पक्ष के पास अपने मनबल मुह हैं और सबने मतदाताओं को लुभाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। तो मतदाता भी पूरे मन से मतदान के लिए निकले हैं।

इस बार यह भी खास गौर करने की बात है कि दोपहर एक बजे तक ही मतदान का आंकड़ा 42 प्रतिशत के पार पहुंच गया था। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें पचाही देरी लगी थी कि बिहार के लोगों के लिए इस चुनाव का क्या महत्व है? आज बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और मतदाताओं की जिस तरह से खुश करने की कोशिश हुई है, उससे पता चलता है कि जोई कोई भी, बिहार में सत्तारूढ़ को कांग्रेसी और गिरि बलवाने वाली है। लोगों की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। फिलहाल, मतदान की चर्चा करें, तो दोपहर एक बजे गोपालगंज में जब मतदान 47 प्रतिशत को छू रहा था, तब पटना में मतदान 37 प्रतिशत तक पहुंचा था। इसका मतलब है कि छोटे शहरों और गांवों में मतदान के प्रति उत्साह है। अक्सर यह कह दिया जाता है कि ज्यादा मतदान का एक संकेत सत्ता परिवर्तन होता है, पर

बिहार में हर दल के पास अपने मनबल मुड़े हैं और सबने मतदाताओं को लुभाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। लोग भी पूरे मन से मतदान के लिए निकले।

विगत दशक में अनेक मीढ़ें एक-एक कर, जब ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के पक्ष में गया है। आप-एच सकेत है कि महिलाओं को वोट नीतीश कुमार के पक्ष में ज्यादा पड़ते हैं और इस बार मतदान में महिला भागीदारी ज्यादा दिख रही है। हालांकि, ये सामान्य विश्लेषण है, जो परिणाम के बाद किनारे धरे रह जाएं, तो आश्चर्य नहीं। भागी मतदान से कोई भी सुनिश्चित संकेत निकालना समझदारी नहीं है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि जिन 18 जिलों में मतदान हुआ है, वहां कभी मतदान के समय तनाव और हिंसा की आशंका रहती थी, लेकिन इस बार फिर चुनाव आयोग की तैयारी कामयाब दिख रही है। मतदान से काफी दिन पहले ही केंद्रों के आसपास जिस तरह से अदृश सैनिक बलों की सहायता से सुरक्षा प्रबंध किए गए, उससे शांतिपूर्ण मतदान में सहूलियत हुई है। हालांकि, कुछ जगहों पर शिकायतें आई हैं। आजद की ओर से एक आरोप यह लगाया गया कि मतदान केंद्रों पर बार-बार बिजली कटने से असर पड़ा, हालांकि, इस आरोप से चुनाव आयोग ने साफ इनकार किया। उदा. अन्य शिकायतें खरौंसर से हैं, जहां उम-मुहम्मद विजय सिन्हा और एक राजद विधायक के बीच संघर्ष पर झूझ भी गई। ऐसी झड़प से चचना चाहिए। यह अनिश्चित परंपरा है कि चुनाव या मतदान के समय प्रतिद्वंद्वी नेताओं को आने-सामने आने से चचना चाहिए। अगर ये में शांतिपूर्ण व समूल चुनाव बिहार की एक विशेषता बन जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 07 अक्टूबर, 1950

दूध की समस्या

कहा जाता है कि पुराने जमाने में भारत में दूध और चीर को नर्त्यां बहती थी। इस कथन को अक्षर: लेने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ये पदार्थ हमारे देश में प्रचुर मात्रा में सुलभ थे। आज भी यह बड़े-बड़े सड़क की गमलों की तरह उन्नी-उन्नी स्वरों से बह नमना देता है। जन भारत के देशों में दूध बेचना पाप समझा जाता था और अजन्मी अतिथि निःशुल्क बह पदार्थ प्राप्त करते थे।

किन्तु अब स्थिति इतनी बदल गई है कि देशों में दूध के दरान दुर्लभ हो गये हैं। इस पर-पन्ना और सौ-सौ गैलन की दूध पर स्थित देशों की दूध स्थिर करने वाली मशीनों के लिए चर्चा चल रही है। जिन घरे में दूध पैदा होता है, उसका बर्तन को वह नसीब नहीं होता। नमरी में जो दूध लोगों को नमदानी है, उसका दूध का नाम देने में भी संकोच होता है। उसके संवेग में नहीं कभी नमदानी है कि दूध में पानी मिलाया गया है अथवा पानी में दूध। दूध में मिलावट किस हद तक बढ़ गई है, यह सचकार के उच्चाधिकारियों ने भी छिछोरे नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार के कृषि-पर्याय विकास सचकार अपनी योजना परिपक्व कर रहे हैं। दूध में पानी और मिलावट निकले दूध की मिलावट भारत में एक आम बात हो गई है। दूध में मैदा और अरोस्ट मैदा पदार्थ को मिला दिया जाता है, जिससे दूध की परीक्षा करने वाला घन मिलावट को नहीं पकड़ पाता। दूध में मिलावट इतनी व्यापक हो गई है कि अलयोग प्रभाव-इसकी परवाह ही नहीं करते। भारत सरकार के सलाहकार के इस कथन में नितक भी अनुत्पन्न नहीं है।

अब तक हुए भी-क्लिन्कल परीक्षण में जीआरपी आधारित वैक्सीन को भी नहीं पर अच्छे नतीजे दिखाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीआरपी वैक्सीन को जेनो-पाटिकरुस और एडजुवेंट (जो इन्फ्लुएंजा को और तेज करते हैं) के साथ मिलाकर, अगर अत्यंत चतुरता बनाया जा सकता है। इसके अलावा, होकर सीजन के ट्यूमर से जीआरपी कोम्लेक्स फसलकर परेनलहाइड वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है। इससे इम्यून और सटीक हो जाएगा। भारत के कैसर अंतुसंगम केंद्र (सीसीआर) के शोधार्थी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति

वें मातृ... यह केवल उच्चतर शब्द नहीं है, यह भारतीय आत्मा का वह शास्त्र निनाद है, जो डेढ़ शताब्दी से अनवरत गुंजित हो रहा है। यह भारत गीत नहीं, राष्ट्र-जागरण का वह दिव्य महामंत्र है, जिसने पराधीनता की बंधुओं में जकड़े भारत को आत्मबोध का प्रकाश दिया, निराशा के भार तमसे में अंधिमारी की ज्वालि प्रज्वलित की, संघर्ष को संभव और स्वाधीनता को स्वरूप प्रदान किया।

इस गीत में न तो सत्ता का मोह है, न किसी जाति, संस्था या प्रांत का अहंकार। यह गीत संपूर्ण भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह चेतना, जो हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म से निर्मित हुई है। इस गीत ने हमें यह सिखाया कि राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवन्त, संवेदनशील, मातृस्वरूप सत्ता है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण ही हमारी असली पहचान है। यह गीत भारतीय जीवन-दर्शन का प्रतीक है, जहां राष्ट्रभक्ति केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और सेवा का रूप ले लेता है।

वें मातृ... यह कल्पना के रत्न अपने आप में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। जब ब्रिटिश शासन भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का प्रयास कर रहा था, तब बंकिमचंद्र ने अपने उपन्यास *आनंद मठ* में इस गीत को स्थान दिया। आनंद मठ के संघर्षालो यह गीत गत है। यह 'संन्यासी विद्रोह' को प्रेरणा बना, जिसने ब्रिटिश सत्ता के सामने भारतीय आत्मबल का पहला प्रतिहार खड़ा किया। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने सन् 1875 में जब इस गीत को रचना की, तब उन्होंने केवल काल नहीं लिखा, उन्होंने राष्ट्र की रोंछें डींगें को अपना का संस्कार किया। *मुकुलम् हुण्डम्पुम मलयनयौलाम्पु शस्ययामलाम्पु मातृम्पु* की ध्वनि ने भारतीय मातृस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी।

कैंसर के इलाज में बड़ी उम्मीद बन रही इम्यूनोथेरेपी

आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। चिकित्सा विज्ञान में आजकल कई अलग पद्धतियों से कैंसर का उपचार किया जाता है और ये पद्धतियां कई मामलों में कारगर भी साबित हो रही हैं। इनमें से ही एक पद्धति 'इम्यूनोथेरेपी' है। इसमें कैंसर से लड़ने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत बनाया जाता है।

इम्यूनोथेरेपी में रोगी के रोग प्रतिरोधक प्रणाली (इम्यून सिस्टम) में सामान्य ट्यूमर/मेटास्टासिस वाले कैंसर, जैसे ब्रेस्ट आरएनएफ का उपचार किया जाता है। परंपरागत, इसका लक्ष्य इम्यून सिस्टम को इस प्रकार से सक्रिय करना है कि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उनका मुकाबला कर सके। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन प्रभावित कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल के वर्षों में जीआरपी (ग्लोबल रीसेल्यूट प्रोटॉल) आधारित वैक्सीन एडजुवेंट्स से लक्ष्यक ध्यान रखा है। पैनलिया का यह वैक्सीन कैंसर के इलाज और रोकथाम में बड़ी भूमिका निभा सकती है। जीआरपी हमारे शरीर में मौजूद एक खास प्रकार के कोशिका होते हैं। ये कोशिकाओं को

को मानव से बचाते हैं और प्रतिद्वंद्वी की सही आकार देने में मदद करते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय करते हैं। जीआरपी शरीर की प्रतिद्वंद्वी कोशिकाओं को कैंसर की पहचान करने और उसे नष्ट करने की क्षमता बढ़ाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर को पूरे कैंसर एंटीजन को जानकारा देता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कैंसर की पहचान कर उस पर तेजी से हमला कर सकें। यही वजह है कि जीआरपी-170 को भविष्य की कैंसर वैक्सीन के लिए 'गैसचेंजर' माना जा रहा है।

अब तक हुए भी-क्लिन्कल परीक्षण में जीआरपी आधारित वैक्सीन ने वृद्धों पर अच्छे नतीजे दिखाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीआरपी वैक्सीन को जेनो-पाटिकरुस और एडजुवेंट (जो इन्फ्लुएंजा को और तेज करते हैं) के साथ मिलाकर, अगर अत्यंत चतुरता बनाया जा सकता है। इसके अलावा, होकर सीजन के ट्यूमर से जीआरपी कोम्लेक्स फसलकर परेनलहाइड वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है। इससे इम्यून और सटीक हो जाएगा। भारत के कैसर अंतुसंगम केंद्र (सीसीआर) के शोधार्थी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति

राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर आत्म-निरीक्षण का क्षण भी है। क्या हम उस भाव को जी पा रहे हैं, जिसके लिए असंख्य देशभक्तों ने प्राणों की आहुति दी?



सन् 1905 के वंग-भंग आंदोलन के समय *वंदे मातरम्* एक गीत नहीं रहा। इसकी गूंज विद्यालय, सभाओं, जुड़सों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी, जहां स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फंसे के तख्ते पर चढ़ते क्रांतिकारियों के होठों पर आँसु आँसु। यह गीत 'वंदे मातरम्' ही था। मुहूर्तव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया, तो वह केवल गीत नहीं रहा, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गया। *वंदे मातरम्* ने धर्म और देशप्रेम को एक स्वर में बांधा, जिससे भक्ति और देशभक्ति एक ही धारा बनकर बहने लगी। इसी भावना ने लखौं भारतीयों को उस स्वाधीनता यज्ञ में आहुति बन जाने की प्रेरणा दी, जिसकी लौ से भारत ने स्वतंत्रता का संदेश दे दिया।

स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने भी इस गीत को राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक बना। यही कारण है कि *वंदे मातरम्* आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए श्रद्धा और गर्व का विषय है। यह गीत कालांतर है, क्योंकि इसमें न तो किसी युग का बंधन है, न किसी प्रदेश की सीमा। इसमें उस भारतमाता की दिव्यता झलकती है, जो केवल भूभाग नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति व सनातन चेतना का जीवन्त रूप है। आज जब हम *वंदे मातरम्* की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का पावन अवसर मना रहे हैं, तो केवल स्मरण का नहीं, बल्कि आत्मालोकन का क्षण भी है। क्या हम उस भाव को जी पा रहे हैं, जिसके लिए असंख्य देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी? क्या हम अपने जीवन में वही संस्कार, वही अनुभूति और वही मातृभूमि-भक्ति स्थापित कर पाए हैं?

दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बहुत कम लोग बूढ़िजीवी *वंदे मातरम्* पर प्रामाणिकता के साथ साक्षर होते हैं। कभी इसे रीढ़-प्रवृत्ति न केवल अज्ञान और एंग्लोसैक्सन ने जोकर बनाया, बल्कि राष्ट्रभक्ति को संकुचित किया। आज भी राष्ट्रप्रति न केवल अज्ञान और एंग्लोसैक्सन (इंग्लिश) को उपयुक्त है, बल्कि राष्ट्रभक्ति व सांस्कृतिक परंपरा प्रति यह अंधकार का प्रतीक भी है। वस्तुतः *वंदे मातरम्* किसी मात्र, पंथ या संप्रदाय का

इसमें उस भारतमाता की दिव्यता झलकती है, जो केवल भूभाग नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति व सनातन चेतना का जीवन्त रूप है। आज जब हम *वंदे मातरम्* की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का पावन अवसर मना रहे हैं, तो केवल स्मरण का नहीं, बल्कि आत्मालोकन का क्षण भी है। क्या हम उस भाव को जी पा रहे हैं, जिसके लिए असंख्य देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी? क्या हम अपने जीवन में वही संस्कार, वही अनुभूति और वही मातृभूमि-भक्ति स्थापित कर पाए हैं?

दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बहुत कम लोग बूढ़िजीवी *वंदे मातरम्* पर प्रामाणिकता के साथ साक्षर होते हैं। कभी इसे रीढ़-प्रवृत्ति न केवल अज्ञान और एंग्लोसैक्सन ने जोकर बनाया, बल्कि राष्ट्रभक्ति को संकुचित किया। आज भी राष्ट्रप्रति न केवल अज्ञान और एंग्लोसैक्सन (इंग्लिश) को उपयुक्त है, बल्कि राष्ट्रभक्ति व सांस्कृतिक परंपरा प्रति यह अंधकार का प्रतीक भी है। वस्तुतः *वंदे मातरम्* किसी मात्र, पंथ या संप्रदाय का

मनसा वाचा कर्मणा

अपने भाग्य का फैसला

भाग्य ऐसी चीज है, जिसे आप अचेतन में निर्मित करते आते हैं। आप इसे संतर्पण में भी निर्मित कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। आप कौन जाना चाहते हैं, आप वह क्या, अपना मार्ग और मंजिल खुद चुनते हैं। यह आपके हाथ में है। अगर आप अपने अंतर्गत को धृं सके; अगर एक क्षण के लिए अनुभव कर सकें कि अपना भाग्य खोल आप के हैं और संपूर्ण ध्यान वस्तु पर लगा सकें, तो आप अपना भाग्य दोबारा लिख सकते हैं। वास्तव में, आपका ध्यान हमेशा बिखरा रहता है, क्योंकि जिसे आप 'मैं' मानते हैं, वह आपका शरीर, आपकी चेतना, पंती, निष्ठा, आपका ओहदा और आपकी अन्य सभी पचातन हैं। अगर मैं आपको दो चीजें चीजों से अलग कर दूँ, शरीर और मन से भी अलग कर दूँ, जिन्हें अपने अकड़ा कर दूँ, तो आप ऐसा महसूस करेंगे, जैसे आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो आप इसे 'आप' में कहते हैं, वह अभी आपके चारों तरफ फैला हुआ है।

जब मैं 'आप' कहता हूँ, तो वह स्थिति 'आप' है। अगर इस पर अपना ध्यान लगाएँ, तो आप जिस तरह से चाहेंगे, अपना भाग्य फिर से लिख सकते हैं। अभी, जो 'आप' है, वह फैला हुआ है। आप इसे देखें और आप इसे देखें। आप अपने अंदर स्थिति नहीं हैं। आपको अब भी सारे कर्तव्यों को बदलने पड़ता है। फिर वह कचरा आप बन जाता है। आप अभी भी अपनी बहन पाए हैं; आप एक भौड़ हैं। एक भौड़ का भाग्य हमेशा पहले से निश्चित होता है। जैसे ही आप एक व्यक्ति (इंडिविजुअल) बन जाते हैं, आप अपने भाग्य के स्वामी हो जाते हैं।

दोष, इस शरीर के साथ बंधन किन्ना हारा है। यह सभी आसक्तियों का खोस है। आपको अनारसक्ति



दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है; क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र है, स्थिर मुजबूत शासन है। यहां के कार्यबल में जैसे-जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, भारत आगे बढ़ा है। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी।

आम जनता को आगाह करते आंकड़े

आपको पता है, डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) किसे कहते हैं? जिसमें जनता अपनी कल्पना खुले चुने, पर कौन सी जनता? पर मैं लेटी जनता नहीं, खड़े मन का मत की जनता नहीं। फेकटरी या कंपनी में फिर जनता जनता नहीं। विनयेस पर फिर कौन सेंटर से जुड़ी हुई जनता नहीं। जानते हैं, वह जनता कौन होती है, जो लोकतंत्र को पहचाने? वह जनता होती है "मतदाता-सूची" में जिनका नाम हो। जो वोट कर सके। जिनकी, सारा लोकतंत्र ही मतदाता-सूची पर टिका है और वही अब स्थिति हो रही है। आपको यह अधिकार मिला था, जिसे चाही उसे चुनिए। यह अधिकार अगर दमक चढ़ गई, तो फिर सिरों की गिनती में तो रहे, मगर कोई अधिकारी नहीं रहे।

राहुल गंधी ने सही श्रेष्ठत से अपने संसर्पण का इस्तेमाल करके वे खुलसते किए हैं। इसकी गंभीरता की समझिए।

चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था, उसे पहले इसकी जांच करनी चाहिए। यह तमाशा नहीं है, या जो जांच करे राहुल को पाला साबित कीजिए या फिर जांच छोड़िए। आज जो राहुल को नमस्कार कर रहे हैं, वे अपने भविष्य को नमस्कार कर रहे हैं। जो इस पर गंभीर नहीं है, वे अपने ही लिए गंभीर नहीं। जिन्हें राहुल पर हंसी आ रही है, वास्तव में वे अपने ही ऊपर हंसी रहे हैं। देश वन के एक पहलू ने नेता प्रतीक्षा ऐसा मिला है, जो लोकतंत्र और ईशानों की बराबरी को लेकर डरना सज्ज है। जो राज जनता को जगा रहा है। जो भयंकर समर सहकर भी जुझ रहा है। उसे नमस्कार करके आप अपना ही मुकाम कर रहे हैं।

राहुल की बात उन युवाओं को तक जकड़

अनुलोम-विलोम कथित वोट चोरी



वोट चुराने के आरोप विश्वसनिय नहीं

पस में नहीं दाने (साख), राहुल चले भुनाने (उत्सव/भड़काने)। वह जलाल की मांडल द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डालने का प्रमाण तो चुनाव आयोग को है, तब आम जनता को वोट बात पर एक आना भी विश्वास करेगी। 22 बार वोट डालने की तो बात ही छोड़िए। वह प्रमाण देना कोई बहुत कठिन कार्य होगा। नतीजा भी नहीं है। कोरिस के पास मतदान केंद्र का मतदान वाले दिन का रजिस्टर होगा, जो उसके पोलिंग एजेंट की लिप्ता होगा। साथ ही चुनाव आयोग, अन्य सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्यक्षी के पास भी वह रजिस्टर होगा। इससे पता चल जाएगा कि मांडल ने वोट डाला या नहीं? उनको वह पता ही होगा कि मतदान केंद्र पर हर मतदाता की पहचान मतदाता पत्राचार पर, आधार या अन्य पहचान पत्र द्वारा की जाती है और

फिर संलुट होने पर ही उसे वोट गिनाने दिया जाता है। वैसेही, हर राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्यक्षी के पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र के अंदर बिठाया जाता है। राहुल गंधी आखिर क्यों से ससझाई क्यों नहीं पता करते हैं?

अशोक कुमार गोयल, टिप्पणकार

हरामा गया है। राहुल गंधी ने हरियाणा की मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं, लेकिन वास्तव यह उनका ही देश, जो मतदाता सूची को शुद्धि करने होत है, तब कोरिस विरोध क्यों करते हैं? मतदाता सूचियों की शुद्धिओं को हर करने के लिए ही मतदाता आयोग ने देश के 12 राज्यों में गहन पुरस्कार अभियान शुरू किया है। मगर कोरिस आयोग के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि अगर राहुल गंधी फौजी वोटों के आधार पर भाग्य की जीत का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर मतदाता सूची को शुद्ध करने का विरोध भी करते हैं। सवाल यह भी है कि बिना तब विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची शुद्धि नहीं हो। हरियाणा में कोरिस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? एस पी मित्तल, टिप्पणकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 18 अंक 224

सुरक्षा को प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ में विलासपुर के निकट एक स्थानीय मेमू (मैनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) सवारी गाड़ी और एक मालगाड़ी को टक्कर में देना को रेलवे सुरक्षा तैयारी को एक बार फिर सबालों के घेरे में ला दिया है। शुरुआती जांच बताती है कि यह दुर्घटना तब हुई जब सवारी गाड़ी खरने का निशान दिखा रहे सिग्नल को पार कर गईं। यह बताता है कि इसमानी गलतियों और सिग्नलिंग में चूक भारत के विशाल रेल नेटवर्क में अभी भी एक बड़ी कमजोरी है। यह दुर्घटना उस समय हुई है जबकि केंद्र सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में 900 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने के लिए 24, 634 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है। बहरहाल, रेल लाइनों के विस्तार में सुरक्षा को दृष्टिकान नहीं कर सकता है।

यह सही है कि उल्लेखनीय रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2019-20 के 55 से घटकर 2024-25 में 31 रह गई है लेकिन ऐसी हर घटना बताती है सुरक्षा के मामले में अभी काफी कुछ जाना बाकी है। वित्त वर्ष 26 के बजट अनुमानों के मुताबिक सरकार ने 2025-26 में सुरक्षा के मामले पर खर्च के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। इस राशि का पांचवां हिस्सा पटरियों में नीवीकरण पर खर्च होना है। कुल रेलवे खर्च के प्रतिशत के रूप में सुरक्षा पर होने वाला खर्च वित्त वर्ष 19 के 27 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 26 में 21 फीसदी रह गई।

आधुनिकीकरण के उपाय मल्लान स्वदेशी टकरावरोधी व्यवस्था 'क्वच' की स्थापना, ट्रैक सर्किटिंग और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का विस्तार सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। हालांकि इनका क्रियान्वयन अभी भी असंगत और अधूरा बना हुआ है। वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में भी कहा गया था कि इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग के लिए एलिफैंट 62 स्टेशनों में से केवल 25 पर ही वित्त वर्ष 25 में काम पूरा हो सका। 37 अन्य का उन्धान बाकी है। अभी मालवहन और घने यात्री परिवहन दोनों का प्रबंधन इस चुनौती को और कठिन बना रहा है जबकि कर्मचारियों में थकान भी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है।

बहरहाल, चाहे जो हो रेलवे ने तकनीकी के क्षेत्र में उसाहजनक वृद्धि हासिल की है। भारतीय रेल और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कारपोरेशन गाँधी इकाई लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के बीच हालिया गठजोड़ का इरादा ऑटोमेटिकल टेलिग्रेस और मशीन लॉक की मदद से रेलिंग स्टॉक और पटरियों को जांच करने का है। हर तरह की क्रॉसिंग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि ट्रेनों की भिड़ंत जैसी घटनाओं को टाला जा सके। हालांकि, इन बिजनेस हूब प्रयासों को एक करने की आवश्यकता है ताकि तकनीक, अधोसंरचना और इसनी कारकों को जोड़ने वाली सुरक्षा रणनीति कायम की जा सके।

सुरक्षा के लिए बहुमुखी रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले डिजिटल सिग्नलिंग का व्यापक इस्तेमाल शुरू करना होगा और सरकार जैसे फिडेंट रोकने वाले उपायों को ऐसे सभी रूटों पर लागू करना होगा जहां जोखिम बहुत अधिक है। दूसरी बात, सेंसर और ऑटोमेटिकल इंटरलॉकिंग की मदद से अनुमान लगाकर मरम्मत करनी होगी और पहले ही समस्याओं का पता लगाकर होगा। तीसरा, कर्मचारियों के प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। काम के बेहतर हालात, थकान की निगरानी, ऑटिफिकल लोको पावरल की भाँती और नई तकनीक को लेकर विशेष प्रशिक्षण की मदद से मानवीय चूक में भार कम की जा सकती है। चौथी बात, हर विस्तार या आधुनिकीकरण परियोजना के लिए स्वतंत्र सुरक्षा जांच जरूरी की जानी चाहिए। ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि सिग्नलिंग, ब्रेकिंग और आपातकालीन प्रणालियाँ अधोसंरचना की क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रख सकें।

इसमें दो राय नहीं कि भारत को अधिक रेल प्रोटिओ को तैयार करने और विस्तृत संपर्क व्यवस्था की आवश्यकता है। परंतु सुरक्षा के बिना तेजा गति कोई कामयाबी नहीं है। नई रेल लाइन के हर किलोमीटर के साथ लाखों को सिर्फ तेज से 'सुरक्षित और तेज' की ओर ले जाने की आवश्यकता है। देश में रोजाना सफर करने वाले 2.4 करोड़ रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रणाली में विश्वास केवल सुरक्षा का विस्तार पर नहीं बल्कि इस आश्वासन पर टिका है कि आगामी यात्रा सुरक्षित है।

आज की दुनिया में जी2 महज कागजी

आज का जी2 अर्थात दो महाशक्तियों वाली व्यवस्था बुनियादी तौर पर अस्थिर है और उसमें पूरी दुनिया को प्रभावित कर पाने की ताकत नहीं है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं आर जगन्नाथन

चीन

चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग के साथ अपनी हालिया बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दो महाशक्तियों (जी2) के नेतृत्व वाली एक नई विश्व व्यवस्था की संभावना जताई। उनका कहना यह था कि ये दो महाशक्तियाँ मिलकर दुनिया पर राज कर सकती हैं और यह तब तक सकती हैं कि सभी के लिए क्या सही है।

बहरहाल, 2025 का जी2 आंशिक रूप से एक भ्रम हो सकता है। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन, हाइब्रन और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े तकरीबन हर मुद्दे पर एक दूसरे के विपरीत नजरिया है। एक बात स्पष्ट है कि जी2 और जी2 दोनों जानते हैं कि उनके भौगोलिक दबदबे का क्षेत्र वर्तमान स्तर से बढ़ नहीं सकता है। वेनेजुएला को अमेरिका की धमकी बाकी है कि वह अमेरिकी महाद्वीप में अपने प्रमुख को लेकर किताबें खिंचे हैं और चीन को पता है कि वह भारत या जापान को एक सीमा से अधिक परेशान नहीं कर सकता है। किसी पता यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद रूप पर उसका किताबें प्रभाव दिखाई देगा?

वह विश्व युद्ध के बाद उभरे जी2 के हालात से एकदम अलग है। उस वक़्त भी अमेरिका ही इकलौती सैन्य और आर्थिक महाशक्ति था और करीब एक दशक तक हालात जी1 जैसे हो रहे। उसके बाद ही सोवियत संघ परमाणु शक्ति बना और दूसरी महाशक्ति बना सका। उसने समजावदी विचारधारा के आधार पर बहुत तेजी से सैन्य और आर्थिक क्षमता हासिल की। उसे एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नए-नए स्वतंत्र हुए उपनिवेशों और गरीब देशों का भी साथ मिला। इसके बावजूद सोवियत संघ कभी पूर्ण आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सका और हम अभी भी हालात को जी2 नहीं बल्कि जी1.5 ही कह सकते हैं। बावजूद इसके कि 1990 के दशक के आरंभ तक सोवियत संघ की अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था। उसे यह भूमिका देने में उसकी मजबूती से अधिक शेष विश्व की कमजोरी जवाब दी।

परंतु चीन और अमेरिका वाला आज का जी2 व्यापक शक्ति संतुलन के मामले में आज केवल समतुल्य है और सैद्धांतिक तौर पर यह तभी वास्तविक जी2 हो सकता है जबकि उनके लक्ष्य कुछ खास पर साझा हों। सैन्य और आर्थिक शक्ति के मामले में अमेरिका आगे है लेकिन वह बढ़त आंशिक रूप से एक भ्रम है। कारण: वह केवल तभी काम आता है जब हम

आर्थिक शक्ति को डॉलर में अंकिं। इकोनॉमिक यह है कि अमेरिका के पराभव के साथ ही डॉलर में भी गिरावट आएगी। क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के मामले में चीन पहले ही अमेरिका से आगे है और तकनीक के मामले में भी वह तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अमेरिका और चीन को ज्यादा से ज्यादा जी1 1.75 कहा जा सकता है क्योंकि दोनों ही पक्षों में पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है बशर्ते कि वे एकजुट न हो जाएं। फिलहाल तो इसकी संभावना भी नहीं नजर आती है। वे एक ही विचार पर समझ नजर आते हैं और वह है भारत के उदय को धीमा करना। परंतु वे ऐसा पहले से करते आ रहे हैं। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही करना चाहते हैं।

1990 के दशक के पहले के जी2 और आज में अंतर यह है कि पहले दोनों ध्रुवों के चारों ओर केवल अनुसरण करने वाले मुस्क ही होते थे। युद्ध के बाद का यूरोप तब पड़ा था, और बाकी दुनिया औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़ने और चीन के रूप में उभरने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर यूरोप के लोग का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बसता था। अगर, अगर अफ्रीका के बहुत छोटे या अत्यधिक गरीब देशों को छोड़ दें, तो एशिया में प्रमुख आर्थिक और सैन्य

शक्तियाँ उभर रही हैं। समय के साथ यूरोपीय शक्तियाँ और जापान भी, जो लगभग एक सदी से अमेरिका के इशारे पर चल रहे थे, अपनी आवाज फिर से पा सकते हैं। वे भी जानते हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी वे यह बात खुलकर नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी निर्भरता बहुत अधिक है।

अमेरिकी महाद्वीप और पश्चिमी यूरोप में अमेरिका को कोई चुनौती नहीं है। चीन अभी भी एक एशियाई शक्ति ही है तथा भारत और जापान जैसी शक्तियाँ उसे चुनौती देती हैं। आज के जी2 सीमित अर्थों में ही शक्तिशाली हैं। सैन्य और आर्थिक गठजोड़ बकरार है लेकिन कोई बड़ा देश इन दोनों से डरने वाला नहीं है।

आज अमेरिका और चीन एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अमेरिका चीनी उत्पादों पर निर्भर है और चीन अमेरिका के बाजार पर। आर्थिक वार्तावलीका इसका कारण स्पष्ट है। दोनों देश अब एक-दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस परस्परनिर्भरता से कोई पक्ष अनिच्छित लाभ न उठा सके। इसका अर्थ यह है कि बाकी दुनिया को चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनने की जबरन नहीं है और वे दोनों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर सकते हैं, हम से कम प्यार रूप से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में।

वर्ष 2025 में आर्थिक शक्ति भी 1945 की तुलना में अधिक बढ़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति के मुताबिक डॉलर के संदर्भ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 30.5 लाख करोड़ डॉलर की है जबकि चीन की 18.2 लाख करोड़ डॉलर। परंतु अगर आपसी पांच या छह शक्तियों में तुलना करें, तो जापान, भारत, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस को मिलाकर देखा जाए तो वे चीन के समान ही बड़े हैं। परंतु पीपीपी के संदर्भ में से काफी अलग नजर आता है। इस लिहाज से चीन 40.72 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ बहुत आगे है।

अमेरिका 30.6 लाख करोड़ डॉलर और भारत 17.71 लाख करोड़ डॉलर वाला है। अगले पांच देश यानी रूस, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया और ब्राजील का कुल पीपीपी जीडीपी अमेरिका के बराबर है। रूस को अक्सर आर्थिक नाकामी के लिए याद किया जाता है। वह 7.14 लाख करोड़ डॉलर की पीपीपी जीडीपी के साथ भारत के बाद चौथे स्थान पर है। अपनी आंतरिक कीमती के संदर्भ में रूस शायद ही आर्थिक रूप से कमजोर है।

आज का जी2 कागज पर अधिक मजबूत दिखाता है लेकिन 1945 के उलट बाद वाले पांच देश आर्थिक और सैन्य दृष्टि से इतने कमजोर नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाया जा सके। डॉलर के संदर्भ में अमेरिका और चीन दोनों वैश्विक जीडीपी में 42 फीसदी हिस्सेदार हैं। जबकि आईएमएफ के मुताबिक पीपीपी के संदर्भ में उनको हिस्सेदार घटकर 34 फीसदी रह जाती है।

आज का जी2 परिदृश्य मूल रूप से अस्थिर है, क्योंकि कई ऐसे देश या समूह हैं जिनके पास स्वतंत्र रूप से या समूहों में टोना संदेयता की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई वास्तविक जी2 नहीं हो कि केवल अपने हितों में काम कर सके। बड़ी क्षमता है कि भारत विश्व मंच पर बड़ी भूमिका निभा सकता है।

यदि भारत यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप और रूस को यूरोप में साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सके, और यदि जापान, भारत और आसिया मिलकर एशिया में चीन की आर्थिक शक्ति को संतुलित करें, तो हम एक बेहतर दुनिया और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। यदि चीन को एशिया में संतुलित किया जाए और अमेरिका को उत्तर और दक्षिण अमेरिका में उसकी वायव्यीय तक सीमाएं रखा जाए, तो दुनिया में आर्थिक और सैन्य हितों का बेहतर संतुलन स्थापित हो सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बैंकिंग क्षेत्र में आने वाली है सुधारों की नई लहर

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कई मोर्चों पर सुधार की राह पर है। पिछले एक दशक में यह उद्योग लगातार खबरों में रहा है। सबसे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पर्सनलित गुणवत्ता समीक्षा के माध्यम से बड़े भिन्न पर सफाई अभियान चलाया। उसने डूबती पर्सनलित का पता लगाया और यह सुनिश्चित किया कि बैंक उनके समाधान के लिए धनराशि अलग रखें और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाएं। वित्त वर्ष 19 की विभिन्न तिमाहियों में कम से कम तीन बैंकों की सफाई ने-निष्ठापित पर्सनलितियाँ (एनपीए) 25 फीसदी या उससे अधिक थीं, और प्रोविजनिंग यानी प्रायश्चित्त के बाद चार बैंकों का शुद्ध एनपीए 10 से 19 फीसदी के बीच था।

बैंकों को अपनी ऋण मूल्यांकन को जोड़िस प्रबंधन क्षमताओं को भी मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद 11 सरकारी बैंकों (पीएसबी) की वित्त सुधार कार्यवाई (बीएफए) के अंतर्गत रखा गया, जिसके तहत ऋणदाता तब ऋण देने से रोक दिया गया, जब तक कि वे नए के रूप में एकीकृत जनता के बैंक को उसके देने के लिए सही क्षेत्र और उधारकर्ताओं की पहचान का पता करुलाता हासिल नहीं कर सके।

अगला चरण समेकन का था। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2017 में अपने पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का अपने में विलय कर लिया। इसके बाद 2019 और 2020 में पर्सनलित के बीच कई विलय हुए। सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई।

कुछ बैंकों को छोड़कर, जो समेकन अभियान का हिस्सा नहीं रहे हैं, अधिकांश सरकारी बैंकों ने अपना आकार बढ़ा लिया है। उनके पास अधिक खासी पूंजी है तथा वे रिफाई मुनाफा कमा रहे हैं।

पिछले साल सी11 सरकारी बैंकों ने लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष 2025 में उनका समेकित शुद्ध लाभ 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा, जो इसके पिछले वर्ष की तुलना में 26 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। इसमें एनपीए आबोली बनी कर्म 40 फीसदी यानी 70,901 करोड़ रुपये थी।

वित्त वर्ष 2018 की तुलना में किताबें बड़ी बनावत। उस वर्ष सरकारी बैंकों का समेकित शुद्ध घाटा 85,390 करोड़ रुपये था। उससे कम 21 सरकारी बैंकों में से केवल दो ही शुद्ध लाभ अर्जित कर सके - इंडियन बैंक और विलय बैंक (जिसका अंतर्गत 2019 में देना बैंक के संयोजन और विलय हो गया था)। यहाँ तक कि एनपीए में भी उस वर्ष शुद्ध घाटा दर्ज किया गया।

सभी सरकारी बैंकों ने अभी तक अपनी सितंबर तिमाही की आय की घोषणा नहीं की है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उनका सामूहिक शुद्ध लाभ 44,218 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में एक भी सरकारी बैंक का शुद्ध एनपीए 1 फीसदी नहीं था। एनपीए आबोली का शुद्ध एनपीए 47 आधार अंक (बीओएस) था, बैंक और महाद्वीप और इंडियन बैंक, दोनों का शुद्ध एनपीए केवल 18 आधार अंक था।

इस पुष्टिपत्र में सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सुधारों का एक नया दौर शुरू करने के लिए तैयार है। उसने पहले ही निजी बैंकिंग उद्योग के ढांचे में बदलाव शुरू कर दिया है। सबसे पहले अक्टूबर में, केपिबैंक की निवृत्ति संहिता ने सरकारी बैंकों के एनपीए के निदेशों को चयन के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। अब निजी क्षेत्र के उम्मीदवार एनपीएआई के चार प्रबंध निदेशकों में से किसी एक पर के लिए आवेदन कर सकते हैं। शेष तीन पदों के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकर भी आवेदन कर सकते हैं। अब तक ये पद केवल आंतरिक उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शीघ्र पदों के लिए निजी क्षेत्र के लिए भी दरवाजा खोल दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में निजी और सरकारी क्षेत्र, दोनों को ओर से खुला विधान प्रदान किया गया। अंततः कम से कम 10 लाख करोड़ रुपये के कारोबार वाले सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंकों के चार कार्यकारी निदेशकों में से एक निजी

क्षेत्र से आ सकता है। पिछले महीने, एमिरेट्स एनबीडी बैंक (ईएनबीडी) और आरबीबी बैंक के निदेशक मंडल ने एमिरेट्स बैंक द्वारा आरबीबी बैंक के निदेशक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए उसमें 26,850 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमति जताई। ईएनबीडी, आरबीबी बैंक में 60 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी, अपनी तीन शाखाओं का भारतीय निजी बैंक में विलय करेगा और अंततः इसे शेयरधारकों, निधायकों और सरकार की मंजूरी के अधीन एक पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी बनाया। इससे पहले, जापानी दिग्गज कंपनी निवेश ने ये बैंक में 24.22 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी।

हाल में दुनिया को सबसे बड़ी वैकल्पिक पर्सनलित प्रबंधक कंपनी ब्लैकस्टोन द्वारा फेडरल बैंक में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 6,197 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसके अलावा, अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म वारपॉ पर्सनल एलएलसी और अरु धावी डेन्टस्टैट अर्थात् (एडीआईए) आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7,500 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। हम वह देखने के लिए उत्सुक हैं कि आरबीबीआई बैंक का क्या होगा, जहाँ सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की संयुक्त रूप से 94.72 फीसदी हिस्सेदारी है, और दोनों 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बचने की योजना बना रहे हैं।

हालांकि घरेलू निजी बैंकों में विदेशी स्वायत्तत्व की सीमा 74 फीसदी तथा नागरिक 26 फीसदी पर बकरार है, फिर भी निजी बैंकों में विदेशी निवेशकों की भूमिका के संबंध में नियामक के दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से बदलाव आया है। जल्द ही, हम सरकारी बैंकों के क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ देखेंगे। विदेशी निवेशकों को सरकारी बैंकों में ज्यादा हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने की योजना है। तो क्या सरकार इन बैंकों में अपना हिस्सेदारी 51

फीसदी से कम कर देगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन विदेशी हिस्सेदारी, जिसकी सीमा 20 फीसदी है, बढ़ाकर 49 फीसदी की जाएगी।

सरकार इन बैंकों में पूंजी डालती रही है। सरकारी बैंकों को सफाई करने के लिए वित्त वर्ष 2022 तक 4,38,780 करोड़ रुपये डाला जा चुके हैं। यह प्रक्रिया 1980 के दशक के में शुरू हुई थी। सबसे बड़ी कितल वित्त वर्ष 2019 में जरी की गई थी। 1,06,000 करोड़ रुपये थी, उसके बाद वित्त वर्ष 2018 में 90,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020 में 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उस दौर में इस उदार पंजी निवेश के विना, सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ नहीं कर पाते।

मजबूत और लाभ कमाने वाले सरकारी बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के बीच सरकार को कम से कम 54,500 करोड़ रुपये का लाभोशर दिया है। इस समय, सरकारी बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाना सीधा कदम है। इससे उन्हें अपनी पूंजी बढ़ाने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फिलहाल, सरकारी बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी बहुत कम है। यह सबसे ज्यादा केरला बैंक (11.8 फीसदी) में है, उसके बाद एसबीआई (9.56 फीसदी), बैंक ऑफ बड़ोदा (8.71 फीसदी) और गुजरात बैंक ऑफ इंडिया (7.86 फीसदी) का स्थान है। यहाँ बैंकों में यह 5 फीसदी से भी कम है, और कम से कम तीन बैंकों में तो यह कुछ ही आधार अंक है।

सरकारी बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कितनी रही है? न्यूनतम सीमा 51 फीसदी है, लेकिन कम से कम तीन बैंकों में यह 90 फीसदी से ज्यादा है। एसबीआई में यह 55.5 फीसदी है। बाकी बैंकों में यह 62.93 फीसदी से 89.27 फीसदी के बीच है।

क्या सरकार अपनी हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को बेचेगी? नहीं। मेरा अनुमान है कि सरकारी बैंक पात्र संस्थागत निवेशन (क्यूआईपी) और अन्य माध्यमों में नई पूंजी जुटाएंगे। जैसे बैंक मजबूत और लाभ कमाने वाले हैं, इसलिए उनके लिए इन्हें खरीदा होना। हालांकि इसे सार्वजनिक बचने के लिए सरकार को इन बैंकों के संचालन के तरीके पर पुनर्विचार करना चाहिए।

बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा हमने से हलात बढ़ाने। प्रणामश्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बैंकों को व्यावसायिक संस्थाओं की तरह हो माना जाना चाहिए।

आपका पक्ष

इंटीग्रेटेड पेरेंट मैनेजमेंट विधि अपनाई जाए

रासायनिक कीटनाशकों के दुष्परिणाम सामने आने के बाद भी न किसान नई नियंत्रित करने को राजी हैं और न प्रशासन इनकी बिक्री को हतोत्साहित कर रहा है। दरअसल, कीटनाशकों को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड पेरेंट मैनेजमेंट विधि अपनाने की आवश्यकता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें कीटों के प्रबंधन के लिए विभिन्न तरीकों का संयोजन किया जाता है, जैसे कि जैविक नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि परजीवी और शिकारी। इनका उपयोग करते समय निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाता है। सांस्कृतिक नियंत्रण में फसल चक्र, खरबूटा और अन्य कृषि प्रथाओं का उपयोग किया जाता है, जो कीटों के प्रकोप को कम करने में मदद करती हैं। इन कीटनाशकों का चयन करते समय उनकी



खेतों में कीटनाशकों को नियंत्रित करने के लिए रासायनों के बजाय इंटीग्रेटेड पेरेंट मैनेजमेंट विधि अपनाने की आवश्यकता है

व्यापकता, प्रभावशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग करते समय निम्नलिखित को निर्दिष्ट का पालन करना चाहिए और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना

चाहिए। इन कदमों को उठाकर, हम रासायनिक कीटनाशकों को नियंत्रित कर सकते हैं तथा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को रक्षा कर सकते हैं।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पते और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

मलेरी को आमदनी को रही हो, तो कौन समझदार व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम करे अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को छोड़े। उसके लिए असांगत क्षेत्र में काम करना ही मजबूरी है। यह बात अलग है कि बहुत तेजी से गरीबी दूर हो रही है और सामंजस्य स्थापित हो गया है और अर्थव्यवस्था में भी भरपूर वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर स्थिति देश और समय के लिए अच्छी है। अतः असांगत क्षेत्र को लेकर चर्चा बंद हो या फिर जनकल्याणकारी योजनाओं को अव्योदय आधार तक सीमित किया जाए और जो वास्तव में बहुत अधिक गरीब हैं, जनताविश्व क्षेत्रों में रहें हैं, जिनके पास सुदूर क्षेत्रों में रोजगार सृजित नहीं हुआ है, उन परिवारों के जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तार दिया जाए। दिल्ली और महानगरी में जनकल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग के कारण असांगत क्षेत्र को बढ़ावा मिला तब ही

विनोद जौहरी, दिल्ली

देश-दुनिया



फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैंगलूर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (बीआईसीसी) में 'इंडिया कन्फेडेंसियरी शो (आईएमएस 2025)' के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर 'सारांग' मॉडल के साथ सेल्फी लेती युवाव्रता।

